(i) The Waqf (Amendment) Bill, 2025, as reported by the Joint Committee.	**Eight hours to be discussed**
(ii) The Mussalman Waqf (Repeal) Bill, 2024.	**together**
(iii) The Indian Ports Bill, 2025.	**Two hours.**

The Committee also recommended that the House may dispense with the lunch hour on 2nd and 3rd April, 2025, and also sit late to complete the listed business on both days. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I am sorry. The Government said that the Indian Ports Bill will not be taken up during this Session. That is what they said. So it is not three hours in this Session. I just want to clarify it.

MR. CHAIRMAN: Your point is noted. Shri P.P. Suneer.

---

*[*THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI) *in the Chair.]*

The "Tribhuvan" Sahkari University Bill, 2025-*Contd.*

SHRI P.P. SUNEER (Kerala): Hon. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. Sir, I rise to speak on the "Tribhuvan" Sahkari University Bill with a sense of concern. While the University is meant to serve the cooperative sector, its governance structure tells a different story. In true BJP fashion, decision-making is excessively centralised. The proposed governing board is packed with bureaucrats, and not a single expert from the field of education has been included. What does this reveal? A Government that is short-sighted, that does not recognize the importance of educational expertise in running a university, let alone one dedicated to the cooperative movement!

The story of the man after whom this University is named, Tribhuvandas Kishbhai Patel, is a story of grassroots empowerment. The foundations of Amul were laid by him, and it was the technological innovations and social entrepreneurship of Dr. Verghese Kurien and Shri H.M. Dalaya that transformed it into a globally recognized branch. The cooperative movement was strengthened with technology and innovation by Dr. Verghese Kurien and paved the way for India's self-sufficiency

in the dairy sector. That same spirit is the need of the hour - aligning the cooperative movement with technological innovations.

Sir, while the Government pats itself on the back for the rise in start-ups in recent years, how many of these start-ups follow a cooperative ownership model? What incentives has the Government provided to promote cooperative-based start-ups? The answer remains unclear. How does the Government plan to integrate technological advancements with the cooperative movement? That too remains unanswered. The Government must address these concerns. Further, if the Government is truly committed to honouring the cooperative movement, why has the IMRA not been named after Dr. Verghese Kurien, the architect of India's White Revolution? His contributions transformed India into a self-sufficient dairy nation, and I demand that the Institute of Rural Management Anand be named after its founder, Dr. Verghese Kurien, as part of the Bill itself. The cooperative sector cannot be strengthened through mere slogans and bureaucratic control. It needs real investment, real innovation and real participation from those who understand both education and cooperatives. A university in name alone will not serve the movement unless it is structured to embody the true spirit of cooperation and democracy. Thank you.

श्री मयंककुमार नायक (गुजरात): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं कांग्रेस के मित्रों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज अन्य परिवारों के नाम लेने के बजाय माननीय सरदार पटेल जी को याद करके इस सहकारिता आंदोलन में जोड़ने की बात की है, तो मैं कांग्रेस के सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मोदी जी की सोच है कि अंत्योदय की योजना के माध्यम से इस देश में मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी तक विकास पहुंचे। इसीलिए माननीय मोदी जी कार्य कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में उन्होंने सहकारिता मंत्रालय जब अलग किया, तो देश के गृह मंत्री और प्रथम सहकारिता मंत्री के रूप में आदरणीय अमित भाई शाह जी को इसकी जिम्मेवारी दी। उस जिम्मेवारी को लेकर और सहकारिता मंत्रालय में आमूल परिवर्तन लाकर सहकारिता आंदोलन के माध्यम से गांव को मजबूत करने के लिए, गांव में किसान, पशुपालन और सहकारी मंडलियों के साथ जुड़े हुए किसानों और खेत मजदूरों के लिए कार्य किया। इस सहकारिता आंदोलन के अच्छे परिणामों और उनकी आय में कैसे बढ़ोतरी हो, उस दिशा में कार्य करने के लिए जब से यह मंत्रालय बना है, तब से वह कार्य पर लगा है।

माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को जोड़कर उस क्षेत्र को कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए, इस पर कार्य हो रहा है। जब वे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बनाई थी, न्याय क्षेत्र के लिए लॉ यूनिवर्सिटी बनवाई थी, चिल्ड्रन्स यूनिवर्सिटी बनवाई थी और कामधेनु

यूनिवर्सिटी भी बनवाई थी। अलग-अलग क्षेत्रों में विकास करने के लिए और टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। इसी क्षेत्र में स्वर्गीय त्रिभुवनदास पटेल जी, जिन्होंने सहकारी क्षेत्र के आंदोलन की नीव रखी थी और 1940 में जब किसानों का शोषण हो रहा था, तब उन्होंने माननीय सरदार पटेल जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में आंदोलन शुरू किया था। 14 दिसंबर, 1946 को खेड़ा दूध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना की और उसी का प्रोडक्ट अमूल का जो ब्रांड है, उससे न केवल भारत में, बल्कि विश्व के बाजारों में भारत के किसान की बात और किसान का प्रोडक्ट सभी जगह पहुंचा है। 1973 में अमूल की जब 25वीं सालगिरह मनाई गई, तब यह देश की सबसे बड़ी सहकारी डेयरी बन चुकी थी। अमूल सहकारी डेयरी, जिसकी शुरुआत 250 लीटर दूध से हुई थी, आज करोड़ों लीटर दूध गुजरात के माध्यम देश में पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस के शासन में इस मंत्रालय को 300 करोड़ रुपया का आवंटन किया जाता था, मगर मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में इस विभाग को 600 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की राशि दी गई है और इस सहकारिता विभाग को मजबूत करने का प्रयत्न किया जा रहा है, ताकि सहकारिता आंदोलन पूरे देश में जाए और देश के सभी किसान इससे जुड़े। लोगों को जोड़कर इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से उनको शिक्षा देने और नई-नई टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से शिक्षित करके देश और गांव को मजबूत करने के लिए यह बिल लाया गया है। इस बिल के माध्यम से जो नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, उससे करोड़ों दूध उत्पादक किसान और खेत मजदूरों की आमदनी बढ़ेगी।

महिला सशक्तीकरण और उसके लिए सहकारिता मॉडल, यह पूरे विश्व में और पूरे भारत में नंबर वन है। गुजरात में सहकारिता आंदोलन के माध्यम से सेवा सहकारी मंडली के द्वारा किसानों को 2 लाख रुपए दिए जाते थे, जिसे अभी हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए किया है, वह किसानों को ज़ीरो परसेंट ब्याज पर दिया जाता है। पूरे भारत में सिर्फ हमारा स्टेट ऐसा है, जहाँ पूरे किसानों को 5 लाख रुपए का ऋण ज़ीरो परसेंट सूद पर दिया जाता है। करोड़ों किसान इस योजना के माध्यम से अपनी खेत में उपज पैदा करते हैं। खेती की उपज के लिए एमएसपी पर किसान से जो खरीद-बिक्री की जाती है, वह भी इस सहकारी मॉडल के माध्यम से की जाती है। उसकी उपज को खरीदने के लिए सहकारी संस्थाओं को भी यह दायित्व दिया जाता है। यह इतना बड़ा नेटवर्क है कि उसे आधुनिक बनाने, टेक्नोलॉजी के साथ सज्ज करने और दुनिया के मार्केट में अपने किसान के product को value added करने के लिए इस बिल के माध्यम से technocrats के माध्यम से इसे देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। अभी किसान contract farming के माध्यम से नए-नए products बनाता है। Contract farming के माध्यम से किसान का मुनाफा और उसकी लागत पहले से ही तय हो जाती है। इस मॉडल के कारण किसान ज्यादा से ज्यादा उपज पैदा कर सके, नई-नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए-नए आयामों को छू सके, इसीलिए एक यूनिवर्सिटी के माध्यम से नए-नए technocrats इस फील्ड में आएँगे और देश के products को पूरे देश और दुनिया के मार्केट में लेकर आएँगे। महोदय, सहकारी प्रवृत्ति के माध्यम से दूध और दूध के products की तो बात हुई, मगर जो पशु है, उसके गोबर को भी इकट्ठा करके, उसका बैंक बना कर हमारे यहाँ एक मॉडल बना है, जिसमें गोबर गैस के माध्यम से CNG produce किया जाता है और इसके साथ ही, CNG का पेट्रोल पंप बना कर four-wheelers, two-wheelers,

सबमें उसे डालने का काम हमारे बनासकांठा में शुरू हुआ है। सहकारी संस्था के माध्यम से जो किसान के गाय-भैंस का गोबर है, उससे भी उसको आय मिल सके, इस तरह का मॉडल गुजरात में स्थापित किया गया है। अभी इस मॉडल के माध्यम से आधुनिक खेती में sprinkler के माध्यम से किसान खेती करे, जिससे पानी की बचत हो, नए-नए प्रयोग करके सरकारी बैंक और डेयरी जैसी संस्थाओं के माध्यम से किसानों की इनकम बढ़े, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है और सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए हमारे यहाँ गुजरात में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से चाहे मेडिकल कॉलेज चलाना हो, स्कूल चलाना हो, कॉलेज चलाना हो या सैनिक स्कूल चलाना हो, यह भी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से चल रहा है।

महोदय, इस बिल को जिस तरह से माननीय मोदी साहब और माननीय सहकारिता मंत्री, आदरणीय अमित भाई शाह साहब ने पेश किया है, इसके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाने का स्वप्न है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास', इस सूत्र को चरितार्थ करने के लिए माननीय मोदी जी का जो प्रयास है और यह जो बिल लाया जा रहा है, जिसको इस संसद के माध्यम से भारत की जनता के सामने रखा गया है, उसका मैं भरपूर समर्थन करता हूँ। मेरी गुजारिश है कि इस बिल से भारत के जो किसान हैं और किसान के साथ ही जो पशुपालक हैं, पशुपालक के अलावा जितने भी cooperative banks हैं, sugar factories हैं, उनमें मजबूती आएगी और आने वाले दिन के लिए माननीय मोदी जी ने 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाने का जो स्वप्न देखा है, उसको पूरा करने के लिए यह बिल एक महत्व का बिल होगा। इसी बात के साथ, मैं इस बिल का भरपूर समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): धन्यवाद, नायक साहब। श्री संजय राउत जी। आपके पास 3 मिनट हैं।

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र)**:** वाइस-चेयरमैन सर, देश में एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है और यूनिवर्सिटी का विरोध करने का कोई कारण नहीं है और वह भी देश की पहली cooperative university - Tribhuvan Cooperative University**.** त्रिभुवन भाई का नाम cooperative movement में बहुत आदर से लिया जाता था। उनका काम भी बड़ा है और अमूल की स्थापना में उनका बड़ा योगदान रहा।

लेकिन हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर और गुजरात के हमारे सभी भाई जो भाषण कर रहे थे, वे एक व्यक्ति को भूल गए, जिसका नाम है - वैकुंठ मेहता। वैकुंठ मेहता cooperative movement के Pioneer रहे, founder रहे और doyen रहे। वैकुंठ मेहता जी के नाम से महाराष्ट्र के पुणे में एक सबसे बड़ा cooperative management institute है। मोहोल साहब, वह आपके कार्यक्षेत्र में है। Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Management को कांग्रेस की सरकार ने 1967 में बनाया, जिसे VAMNICOM नाम से जाना जाता है। वह 70 साल से काम कर रहा है। वह 70 सालों से वह काम कर रहा है, जो मंत्री जी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से अभी करना चाहते हैं। **...(व्यवधान)...** आप गिन लीजिए, बाद में हम बैठेंगे। वैकुंठ मेहता कोऑपरेटिव इंस्टिट्यूट अपने आप में एक University है और विश्व के लगभग 40 देशों के साथ उसका नेटवर्क

है। पुणे के Savitribhai Phule University से उसका affiliation है। जो युवा cooperative management में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए सभी educational facilities उस VAMNICOM में आज भी हैं । तो मेरा कहना है कि एक नई युनिवर्सिटी बन रही है, इसका स्वागत है, लेकिन वह भी एक युनिवर्सिटी है, उसको भी अगर आप cooperative university का दर्जा देने प्रयत्न करते, तो 2 universities हो जातीं। वैकुंठ भाई गुजरात से थे। त्रिभुवन पटेल यूनिवर्सिटी बनाने का उद्देश्य क्या है - Technical, management education training और Cooperative में research and development. ये सभी faculties वैकुंठ मेहता कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट में चल रही हैं। आप उनका प्रोग्राम देखिए। Cooperative banking, cooperative marketing, housing cooperative, dairy management, cooperative laws, sugar, forest, computers - ये सभी सब्जेक्ट्स वैकुंठ मेहता कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट में आज भी पढ़ाए जाते हैं। Ministry of Human Resource Development, Government of India has recognized the institute as a consultant for evaluating the Women Dairy Projects. देश का best cooperative journal यहां से निकलता है।

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री संजय राउत: वहां एक हॉस्टल है और उस हॉस्टल में 200 कमरे हैं। एक यूनिवर्सिटी के लिए और क्या चाहिए? तो सबसे बड़ा काम वहां चल रहा है। मैं यह मानता हूं कि त्रिभुवन पटेल यूनिवर्सिटी देश के लिए एक मार्गदर्शक रहेगी, अच्छा काम करेगी, लेकिन मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उसके साथ-साथ इस देश में जो Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Management चल रहा है, उसको भी आप इस युनिवर्सिटी से affiliate करिए। देश के लिए एक बड़ी यूनिवर्सिटी बने, हमारे जो युवा इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं या करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी यह आपका एक योगदान रहेगा। इसके साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे (महाराष्ट्र)**:** उपसभाध्यक्ष महोदय, आज त्रिभुवन सहकारिता विधेयक, जो विद्यापीठ का विधेयक है, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। महोदय, माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी, जिनका लक्ष्य सहकार से समृद्धि है, उसको पूरा करने के लिए हमारे सहकारिता मंत्री, माननीय अमित शाह जी और मैं महाराष्ट्र से राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल जी का नाम लेना चाहता हूं, इन्होंने यह जो बिल लाया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। सहकारिता के ऊपर प्रधान मंत्री जी का इतना ख्याल है कि National Cooperative Policy, 2025 के लिए अभी-अभी 6 मार्च, 2025 को उन्होंने एक मीटिंग चेयर की, जिसमें सहकारिता मंत्री थे, सहकारिता राज्य मंत्री थे, सेक्रेटरीज़ भी थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामों की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए और youth तथा महिलाओं को prioritize करने

के लिए Cooperative Policy में क्या बदलाव कर सकते हैं और नई पॉलिसी कैसे ला सकते हैं, वह भी सहकार से समृद्धि की, तो इस सहकार से समृद्धि की जो पॉलिसी है, इसमें सब कुछ आ रहा है। अभिमान की बात ऐसी है कि जिन्होंने सहकारिता की नींव रखी, चाहे वे वैकुंठ मेहता जी हों, त्रिभुवन पटेल जी हों या हमारे महाराष्ट्र में सहकार महर्षि, धनंजय गाडगिल जी, विट्ठल राव विखे पाटील तथा और भी बहुत से लोग हुए.. ये सहकार महर्षियों ने उस वक्त से सहकार से समृद्धि लाने की कोशिश की और आज त्रिभुवन काका पटेल के नाम से जो यूनिवर्सिटी हो रही है, इससे सच में उनका सम्मान हो रहा है। मैं कांग्रेस के लोगों से सच में पूछना चाहता हूँ कि 70 साल में, जिन्होंने अमूल का ब्रांड बनाया, उनका सम्मान करने के लिए ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने की बात उनके दिमाग में कभी क्यों नहीं आई? **...(व्यवधान)...**

श्री संजय राउतः माननीय सुखदेवराव बोंडे जी, महाराष्ट्र में **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी)ः कृपया आप बैठिए। **...(व्यवधान)...**

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे: सर, आपको पता है कि काँग्रेस ने वैकुंठ जी मेहता के नाम से इंस्टिट्यूट बनाया, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी)ः कृपया आप बैठिए। **...(व्यवधान)...**

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे: सर, ये अभी यह डिमांड कर रहे हैं कि उसको affiliate कीजिए, उसको यूनिवर्सिटी बनाइए। यह बात आपके भी दिमाग में नहीं आई। कांग्रेस के दिमाग में तो वैकुंठ जी मेहता का भी सम्मान करने की बात नहीं आयी। पहली बार उनको यह सम्मान मिल रहा है। यह यूनिवर्सिटी अनोखी है, क्योंकि हमें मालूम है कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी रहती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी रहती है, लेकिन Cooperative University of its own kind पहली बार पूरे भारत देश में पहली यूनिवर्सिटी हो रही है। यह सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉरपोरेट यूनिवर्सिटी नहीं है और इसकी फंडिंग भी कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर से होने वाली है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह समझने की है कि इस कोऑपरेशन को अभी ग्लोबल करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि यह स्टेट का सब्जेक्ट है। निश्चित यह स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन सभी स्टेट्स में सहकार उतना समृद्ध नहीं हुआ है, जबकि आज हमें सहकार के माध्यम से global competitiveness में जाना पड़ेगा। अगर global competitiveness में जाना पड़ेगा, तो नॉलेज, इनोवेशन, रिसर्च और ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार मुक्त सहकार, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप और youth involvement - ये सब चीजें जब हम सहकार में लाएंगे, उसमें टेक्नोलॉजी लाएंगे, rules and regulations to become transparent लाएंगे, तभी हम global competitiveness में एंट्री कर सकते हैं। इन सब चीजों के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल के माध्यम से जो यह पहल की गई है, उसके लिए मैं सहकारिता मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूँ। 'सहकार से समृद्धि' मोदी गवर्नमेंट का जो स्लोगन है, यह सिर्फ स्लोगन नहीं है, बल्कि उन्होंने उसमें बहुत सारी चीजें

करके रखी हैं। 63,000 पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी) हैं, जो सब गांवों में हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हैं। मोदी जी के पहले पैक्स का computerization नहीं हुआ। ये सभी पैक्स का computerization करने, उसका पूरा डेटा लेने, उसको एक कॉमन प्लेटफार्म पर लाने, सभी को एक ही सॉफ्टवेयर देने और सभी का जो कार्यभार रहेगा, उसको पूरे ग्लोबल नेटवर्क में रखने के लिए 2,516 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया। मैं भी ग्रामीण इलाके से आता हूँ, सहकार से ही आता हूँ और आपको पता है कि हम प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के बारे में सिर्फ यह जानते थे कि यह सिर्फ खेती के लिए कर्जा देने के लिए है। अब इन्होंने इसका स्ट्रक्चर ही बदल डाला। अभी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जन औषधि भी ले सकती है, पेट्रोल पंप भी ले सकती है, कॉमन सर्विस सेंटर भी ले सकती है। 30,000 कॉमन सर्विस सेंटर पैक्स को दिए गए हैं। इसके तहत 5,000 जन औषधि केंद्र हैं और प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जिसमें खाद भी बेची जाती है और अनाज भी खरीदा जा सकता है, उसको भी पैक्स कर रहा है, यानी ऐसे 28 काम इनको दिए जा सकते हैं। Financial support देने के लिए मोदी सरकार ने सर्टिफाइड सीड, ऑर्गेनिक फार्मिंग और एक्सपोर्ट - इन तीनों चीजों को बनाने के लिए एक सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण किया है। नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत तीन प्रकार के निर्माण किए गए हैं, इसलिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, सर्टिफाइड सीड का कर रहे हैं, उनको वहाँ से अच्छी तरह से हेल्प मिल सकती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बाकी की ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ से बहुत ही अलग है, क्योंकि बाकी की यूनिवर्सिटीज़ में ब्यूरोक्रेसी का influence होता है, फंडिंग कभी-कभी नहीं मिलती है और वहाँ आउटडेटेड करिकुलम होते हैं, जिनका जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन, यह त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एक कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है, यह community driven है, यानी इसके stakeholders सोसाइटी में से आ रहे हैं, सहकारिता में से आ रहे हैं। यह financially sustainable है और इसमें सोसायटी के डिफरेंट सेक्टर्स से equity ली जा सकती है। इस प्रकार की यह पहली यूनिवर्सिटी है और अगर समय मिला तो मैं इसके डिफरेंसेज़ के बारे में डेफिनेटली बताऊँगा। कोऑपरेटिव को आत्मनिर्भर बनाने में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा रोल रह सकता है। देखिए, सहकारिता बहुत पहले से आई है। सहकार क्षेत्र में जो-जो लोग ईमानदार थे, जिन्होंने सोसायटीज़ को भ्रष्टाचारमुक्त रखा, वे लोग अच्छे से प्रकट हो सके, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं रहता था। पहले इसका वार्षिक बजट 112 करोड़ रुपए रहता था, जबकि अभी सेंट्रल का बजट 10 गुना, यानी 1,012 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, 5,000 करोड़ की डेयरी सहकार स्कीम अलग है। Farmer producer organization के लिए 10,000 करोड़ का गवर्नमेंट का अलग से फंड आ रहा है। यानी, ये सब चीजें जब हो रही हैं, तब इसमें भ्रष्टाचार होने की संभावना भी रहती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सहकार से समृद्धि होनी चाहिए, लेकिन सहकार से स्वाहाकार नहीं होना चाहिए। उसके लिए मोदी जी की सरकार 2023 में Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 में अमेंडमेंट लाई। उसमें दो चीज़ें थीं, जिनसे governance में भी transparency आती है और आर्थिक व्यवहार में भी transparency आती है। उसकी वजह से जो

बहुत सारी PACS थीं, जो बहुत सारी Multi-State Cooperative Societies थीं, जो stagnant हुई थीं, वे अब अच्छी तरह से काम करने लगी हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी क्या करेगी? यह cooperative leadership की capacity building करेगी। जो नेतृत्व करने वाले हैं, उनको global atmosphere मालूम होना चाहिए कि US और UK की कोऑपरेटिव्स में क्या चल रहा है और कंपनीज़ में क्या चल रहा है। बेसिकली, रूरल से अटैच करने के लिए यह जरूरी है। कोऑपरेटिव सेक्टर में research and innovation करना इस यूनिवर्सिटी का एक बड़ा काम रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोआपरेटिव में सिर्फ कृषि के हिसाब से ही नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार के स्किल डेवलपमेंट करने हैं। जब दिग्विजय सिंह जी से बोल रहे थे, तो मुझे उनकी बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि पहले कृषि मंत्रालय में ही यह मंत्रालय था। साहब, यह मंत्रालय नहीं था, यह सहकार डिपार्टमेंट था। इसको अब सेपरेट मंत्रालय मिलना और इसके खुद का सेक्रेटरी मिलना, यह बहुत बड़ी बात है, नहीं तो यह पहले कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट होता था। मोदी जी ने एग्रीकल्चर सेक्टर में दो इंपॉर्टेंट काम ये किए हैं कि उन्होंने animal husbandry का भी एक विशेष मंत्रालय बना दिया और उसका एक मंत्री बना दिया। वैसे ही, उन्होंने इसके लिए सहकारिता मंत्री बना दिया और वह भी ताकतवर मंत्री बना दिया। अब सहकारिता में सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं आता, बल्कि इसमें हाउसिंग भी आता है, fisheries भी आती है, animal husbandry भी आता है। Even, घास उगाने वाले भी अब अपना एग्रीकल्चर यूनिट बना सकते हैं। सर, महत्वपूर्ण बात यह है कि कोऑपरेटिव में विमेन का participation बढ़ाने के लिए यह यूनिवर्सिटी काम करेगी। भारतीय कोऑपरेटिव संस्थाएँ सहकारी संस्थाएँ हैं। उनका ग्लोबल कोऑपरेटिव सेक्टर में जितना stake है, especially, US, Europe, G-20 तथा जो एशिया के देश हैं, वहाँ उसको बढ़ाने के लिए यह काम कर सकती है। Integration with national development - हमारा गोल क्या है? हमारा गोल 2047 तक विकसित भारत बनाना है। उस विकसित भारत का गोल निर्माण करने के लिए हमें यह करना बहुत जरूरी है। Increased budget allocation के साथ पूरा नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस, Multi-State Cooperative Societies Act, यानी rules and regulations भी सही करना चाहिए।

उसकी फंडिंग भी करनी चाहिए और इसके अलावा, tax exemption बेहद महत्वपूर्ण है। इनकम टैक्स के सेक्शन 155 के अंतर्गत महाराष्ट्र की शुगर कोऑपरेटिव मिल पर 10 हज़ार करोड़ रुपये का टैक्स बकाया था। इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के पास गए, क्योंकि इतनी बड़ी टैक्स देनदारी के कारण शुगर मिलों का संचालन संभव नहीं हो पा रहा था। माननीय अमित शाह जी ने इस 10 हज़ार करोड़ रुपये के इनकम टैक्स को माफ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) के माध्यम से इन कोऑपरेटिव शुगर मिलों को सशक्त बनाने का कार्य किया।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने एक करोड़ से 10 करोड़ की आय पर लगने वाले सरचार्ज को 12 परसेंट से घटाकर 7 परसेंट कर दिया। Alternative Minimum Tax rate from cooperatives, उसको कंपनियों से compare करके 18.5 परसेंट से घटाकर 15 परसेंट तक किया गया। अब कोई

भी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक करोड़ या तीन करोड़ तक की राशि बैंक से without deduction of tax or TDS निकाल सकती है।

महोदय, कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत बढ़ा है और उसके माध्यम से अच्छे से समृद्धि हो सकती है। महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी ने कहा था - "एक मे सहाय करूं, अवघे धरू सुपंथ", अर्थात यदि हम सब मिलकर कार्य करें, तो हम समृद्ध होंगे। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का यह स्पष्ट दृष्टिकोण है कि "बिना सहकार नहीं उद्धार"।

"अंत्योदय और महिलाओं की एक ही पुकार,
उन्नति का मार्ग है सिर्फ सहकार।"

समृद्धि का मूलमंत्र ज्ञान और तकनीकी से युक्त, पारदर्शी सहकारिता प्रणाली में निहित है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में त्रिभुवन काका पटेल के नाम से एक सहकारी विद्यापीठ स्थापित किया जा रहा है, जो विकसित भारत के निर्माण में सहकारी नेतृत्व को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

अतः मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूँ और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी एवं राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल जी का अभिनंदन करता हूँ। हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों के युवा, महिलाएँ और गरीब नागरिक मिलकर सहकारिता के माध्यम से भारत को समृद्ध बनाने का संकल्प लेते हैं।

धन्यवाद। जय हिंद!

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): मैं भी आपको धन्यवाद करता हूं। डा. फौज़िया खान; अनुपस्थित हैं। श्री सतनाम सिंह संधू।

श्री सतनाम सिंह संधू (नामनिर्देशित): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, इस विषय के साथ मेरा बहुत deep connection है, क्योंकि मैं एक एक किसान का बेटा हूँ और educationist भी हूँ। किसान का बेटा होने के नाते मैंने बचपन से ही सहकारिता लहर के साथ काम किया है, इसके बारे में अपने दादाजी से सीखा, इसको देखा है, इसको जिया है। मैं पिछले 25 वर्षों से education में काम कर रहा हूँ, मैं education की सेवा कर रहा हूँ और इसे जी रहा हूँ। मेरे जीवन में मुझे दो यूनिवर्सिटीज़ स्थापित करने का अवसर भी मिला है और मुझे ऐसा लगता है कि यह विषय मेरे दिल के बहुत करीब है।

सभापति महोदय, यह एक ऐतिहासिक अवसर है, जब भारत दुनिया की पहली domain specific cooperative university स्थापित करने जा रहा है। निश्चित तौर पर, इस विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही भारत कोऑपरेटिव क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा thought leader बनकर उभरेगा।

चेयरमैन साहब, त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी सिर्फ एक academic institution नहीं, बल्कि सहकारिता का global centre of excellence बनने जा रहा है। यह दुनिया की पहली full-

fledged co-operative domain-specific University होगी, जहां co-operative finance, agri business, digital co-operative और startup for specialized courses करवाए जाएंगे। यह विश्वविद्यालय international institutions के साथ भी सहयोग करेगा, जिससे भारत की सहकारी संस्थाएं वैश्विक स्तर पर पहचान बना पाएंगी। इस University की स्थापना से co-operative sector में नई ऊर्जा आएगी, professional human resource तैयार होगा, competent leadership पैदा होगी और world class research के साथ नए अवसर भी पैदा होंगे। यह Bill सिर्फ University की स्थापना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका उद्देश्य co-operative societies को empower करना, उनके operations को transparent बनाना और modern technology का integration करना भी रहेगा।

महोदय, भारत में सहकारिता का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। भले ही देश में पहला सहकारी कानून 1904 में आया, लेकिन भारत में सहकारिता की जड़ें 200 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि आदिकाल से ही सहकारिता हमारे जीवन का अभिन्न अंग रही है। भारतीय समाज की संरचना ही आपसी सहयोग पर आधारित रही है। हमारे गांव, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा सामाजिक ढांचा, सब कुछ सहकारिता पर आधारित रहा है। जब देश में banking system मजबूत नहीं था, तब सहकारिता ही थी, जिसने भारत की आर्थिक प्रगति और financial inclusion को संभव बनाया। भारत के सहकारी model को आज Harvard, World Bank, International Co-operative Alliance और United Nations जैसे वैश्विक संस्थान case study के रूप में पढ़ा रहे हैं। यह हमारे सहकारी आंदोलन की सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

सर, यह प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदर्शिता और मजबूत leadership का परिणाम है कि भारत आज विश्व co-operative leader बनकर उभर रहा है। मोदी सरकार ने 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, जिससे भारत में सहकारी संस्थानों को नई मजबूती मिली। इसके साथ ही श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में landmark, institutional and structural reforms भी किए। सहकारी आंदोलन हमेशा ही भारत के विकास और आत्मनिर्भरता का आधार बना रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी इसने अहम भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे एक आर्थिक और सामाजिक क्रांति के रूप में देखा। स्वतंत्रता के बाद सहकारी आंदोलन ने लोकतांत्रित प्रणाली को मजबूत किया और भारत के विकास model को जन-जन तक पहुंचाया।

महोदय, जब भी भारत में सहकारी आंदोलन की बात होती है, तो गुजरात इसका role model बनकर उभरता है। 1946 में सरदार पटेल, मोरारजी देसाई और त्रिभुवन दास पटेल जी के नेतृत्व में किसानों ने ब्रिटिश सरकार को झुकने पर मजबूर किया और यहीं से अमूल की नींव रखी गई। आज अमूल न केवल भारत में, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा dairy brand बनकर उभरा है। देश में गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान ने भी सहकारी model में बेहतरीन सफलता हासिल की है। मेरा अपना गृह राज्य पंजाब co-operatives का गौरवशाली इतिहास संजोए बैठा है, जो करीब 150 साल पुराना है। सर, पंजाब का Milkfed, Markfed और Punjab State Co-operative Bank जैसी co-operative associations ने देश में आज सफलता की नई मिसालें कायम की हैं। अमूल के बाद पंजाब का Verka देश का दूसरा बड़ा dairy product बनाने वाला

brand है। सर, जैसे-जैसे देश विकास की राह पर आगे बढ़ा, वैसे-वैसे देश में सहकारिता भी मजबूत होती गई, लेकिन इसके चलते कुछ ऐसी घटनाएं भी हुईं, जिससे सहकारिता आंदोलन को ठेस भी पहुंचने लगी। सहकारिता आंदोलन को झटके देने के बाद देश का co-operative sector कुछ परिवारों और दलों के हाथ में आ गया। आदर्श घोटाला, NDCCB घोटाला, पुलपल्ली घोटाला और जाने एक के बाद एक ऐसे कितने घोटालों को अंजाम दिया गया।

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश में cooperative की अहमियत को पहचाना और उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत का cooperative sector एक सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार ने 63 हज़ार PACS के कंप्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपये के projects allocate किए हैं, जिससे किसानों को digital लेन-देन और transparency का लाभ मिलेगा, PACS को farmer-producer organizations में बदलने की योजना से किसानों को सीधे बाज़ार से जोड़कर उनकी income बढ़ाने का एक ज़रिया बनेगा।

महोदय, NCDC के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के लोन की व्यवस्था की गई है, जिससे गन्ना किसानों और चीनी उद्योग को नई ऊर्जा मिलेगी।

महोदय, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गरीब और किसान समर्थक नीतियों का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी cooperative food storage scheme लागू करने जा रहा है, जिसमें कृषि उत्पादन की efficient storage हो पाएगी और किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिल पाएगी।

महोदय, पैक्स के तहत 2,000 जन औषधि केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध होंगी।

महोदय, Molasses पर GST को 28 परसेंट से घटाकर 5 परसेंट करने का निर्णय भी किसानों और शराब उद्योग के लिए लाभकारी साबित हुआ है।

इसके अलावा पैक्स को ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं से भी जोड़ा गया है, जिससे सहकारी समितियाँ पानी समितियां बन गई हैं और जल संरक्षण में भी अपना योगदान दे रही हैं। महोदय, यह स्पष्ट है कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का कोऑपरेटिव सेक्टर को सशक्त बनाने का संकल्प भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

उपसभाध्यक्ष जी, आज भारत में सहकारिता की लहर चल रही है। देश में 8.5 लाख से अधिक सहकारी सभाएं हैं, जिनमें 30 करोड़ से अधिक लोग सदस्य हैं। यह संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। महोदय, सहकारिता का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत विशाल योगदान है। IFFCO और Amul जैसे brands दुनिया के सबसे बड़े सहकारी संस्थानों में शामिल हैं और दुनिया भर के लिए एक मिसाल बनकर उभरे हैं। इसके साथ ही भारत का dairy उद्योग 30 लाख से अधिक किसानों को directly जोड़ता भी है। इसी प्रकार fertilizer cooperatives ने भारत को कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है। इसके साथ ही cooperative banks ने ग्रामीण क्षेत्रों में financial services provide कराई हैं। यह विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र को professional रुप से संगठित करेगा, इसे नए युग की तकनीकों से जोड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों को सहकारिता क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए तैयार करेगा।

महोदय, 'त्रिभुवन' कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि भारत के सहकारी आंदोलन के नए युग की शुरुआत है। 2025 में, जब पूरा विश्व International Year of Cooperatives मना रहा होगा, तब यह विश्वविद्यालय भारत को सहकारिता के क्षेत्र में global superpower बनाने का कार्य करेगा।

महोदय, एक educationist होने के नाते मुझे यह पक्का विश्वास है कि विश्वविद्याल में AI, Blockchain, IoT जैसी आधुनिक तकनीकों को शामिल किया जाएगा, जिससे सहकारी संस्थानों की पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ेगी। इसके साथ ही 'त्रिभुवन' कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की International Cooperative Alliance और top global university के साथ साझेदारी भी बनाई जाएगी, ताकि सहकारिता के क्षेत्र में world-class research and innovation को बढ़ावा मिल सके।

महोदय, विश्वविद्यालय में cooperative start-ups और agri-tech innovations को बढ़ावा देने के लिए incubation centres स्थापित किए जाएंगे, जिससे युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिल पाएं।

महोदय, मेरा यह भी मानना है कि विश्वविद्यालय में climate resilient cooperatives पर भी विशेष पाठ्यक्रम लाया जाए, जिससे सहकारी संपत्तियाँ sustainable agriculture, renewable energy and waste management जैसे क्षेत्रों में नवाचार कर सकेंगी।

महोदय, यह विधेयक सिर्फ सहकारी शिक्षा को ही नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा।

महोदय, मुझे खुशी है कि मैं इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं। उपसभाध्यक्ष महोदय, अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

7.00 **P.M.**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Now, Shri Masthan Rao Yadav Beedha.

SHRI MASTHAN RAO YADAV BEEDHA (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir. On behalf of our party, Telugu Desham Party and our leader and hon. Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu, I stand here to speak on the "Tribhuvan" Sahkari University Bill, 2025. Sir, from around 5,000 Societies in 1911, there are more than 8 lakh Societies at present. Cooperatives across India serve an important role in the development of our country, particularly rural development, financial inclusion, empowerment of marginalized communities. Andhra Pradesh has a rich history of cooperative development with a strong network of agriculture, dairy, and credit

cooperatives. The State has witnessed a significant success in leveraging cooperatives to promote rural development and empower marginalized communities. Our party founder, Nandamuri Taraka Rama Rao Garu, believed in the power of cooperatives, even introduced important legislation regarding the cooperatives. The Andhra Pradesh Mutually Aided Cooperative Society Act, 1995, with a target of promoting self-reliant, responsible, accountable and autonomous cooperative societies with their own bye-laws, thereby making the cooperative movement more vibrant. Shreeja Mahila Milk Producer Company - One shining example of cooperatives in my State of Andhra Pradesh is the Shreeja Mahila Milk Producer Company. It stands as a success story of female-centric, socio-economic empowerment within the dairy sector, globally recognized as the largest woman-owned and woman-managed entity of its kind. Commencing operation with a modest membership of 27, it has achieved a remarkable expansion. Currently, it has a shareholder base of 1,09,000 women, all of whom are rural cattle-rearing practitioners.

Sir, Andhra Pradesh has more than 17,000 cooperatives at present. They would all benefit from training programmes and detailed educational assistance from established institutions such as the proposed Tribhuvan Sahakari University. Sir, through you, I would like to urge the hon. Minister to consider establishing such college or institution in our new capital city of Andhra Pradesh, Amravati. Here, I want to bring to your kind notice one thing. While speaking, hon. MP, Shri Ayodhya Rami Reddy Alla, from YSRCP, made some false allegations in this House. I strongly refute a misleading and factually incorrect statement made by him during his speech on this Bill regarding the resignation of Vice-Chancellors and alleged removal of English medium education in Andhra Pradesh. The claim that 17 Vice-Chancellors were forced to resign by the current Government is completely false and baseless, Sir. Out of 17 resignations, 10 were due to personal reasons.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, कृपया आप विषय से बाहर न जाएं। ...(**व्यवधान**)... आपका समय समाप्त हो गया है। धन्यवाद ..(**व्यवधान**)... श्री सुभाष बराला। ...(**व्यवधान**)...

SHRI MASTHAN RAO YADAV BEEDHA: Please, Sir. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Your time was three minutes. I have given you four minutes. Please sit down. ...(*Interruptions*)...

श्री सुभाष बराला (हरियाणा): धन्यवाद, माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज मुझे बहुत खुशी है और खासकर इसलिए भी खुशी है कि मैं छात्र राजनीति के बाद जब अपने क्षेत्र में काम करने के लिए आया, तब 1995 में मुझे भी कोऑपरेटिव मूवमेंट का हिस्सा बनने का अवसर मिला। अपने क्षेत्र में शुगर मिल के डायरेक्टर, वाइस-चेयरमैन, हरियाणा शुगर फेडरेशन के डायरेक्टर के नाते मुझे इस क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। बहुत सारी समस्याएं इस क्षेत्र में सामने आती थीं। उपसभाध्यक्ष महोदय, हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और आप भी उसी प्रकार के क्षेत्र से आते हैं।

हमने बड़े नजदीक से देखा है और हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से सहकार तो हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, लेकिन वर्तमान समय के अंदर जब पूरी दुनिया के अंदर सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा हो और उसमें भारत की भागीदारी, हमारे हिन्दुस्तान की भागीदारी लगभग 25 प्रतिशत की हो और उसके अंदर कुछ नया करने की कोई योजना बनाने वाला व्यक्ति न हो, तो लगता था कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर हम बात करें, तो हम किसान परिवार से आते हैं, हम देखते आए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की और गाँव की अर्थव्यवस्था अपने आप में सहकार के माध्यम से चलती थी। किसान अपने खेत के अंदर काम करता था, बीज उसका अपना होता था, हल भी उसका अपना होता था, उसको बाकी औजारों की जरूरत पड़ती थी, तो गाँव के अंदर लोहार था, किसी दूसरी व्यवस्था की जरूरत होती थी, तो वह उसको गाँव के अंदर मिल जाती थी। धोबी, नाई वगैरह, अगर हम इन सारी व्यवस्थाओं को देखें, ये सारी की सारी कृषि क्षेत्र के ऊपर आधारित थीं और सहकार की भावना से चलती थीं। किसान के घर के अंदर भी जब पहली बार खेत से निकल कर अनाज आता था, तो सब लोगों के अंदर आवश्यकता के अनुसार, वह जितना उनसे काम लेता था, उसको बाँटने का काम करता था। जब हमारी संस्कृति में ही सहकार रचा-बसा है, तो उस क्षेत्र को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि बहुत साल पहले प्रयास किए जाने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसके बारे में सोचा नहीं गया।

मान्यवर, यह विधेयक स्वाधीन भारत के 75 साल बाद आ रहा है, इसलिए इसका अपने आप में बहुत महत्व बढ़ जाता है। सौभाग्यवश माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारे सहकारिता मंत्री, माननीय अमित भाई शाह जी का मैं बहुत धन्यवाद करूँगा कि उनकी दूरदृष्टि के चलते इसके महत्व को समझा गया और वर्ष 2021 में इसे एक मामूली से विभाग के स्थान पर स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा प्रदान किया गया।

महोदय, अभी हम सब लोग देख रहे थे कि अनेक बार इसी सभा में cooperative federalism की बात बड़े जोर-शोर से की जाती रही, लेकिन जब इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए यह त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का बिल इस हाउस में आने से लेकर अब तक की चर्चा की बात करें, तो इस बिल की कितनी ही आलोचनाएँ हुई हैं। कोई इसके नाम को लेकर आलोचना कर रहे थे, क्योंकि 'त्रिभुवन' जो नाम है, उस नाम से जो परिचित नहीं हैं, उनके मन के अंदर तरह-तरह की शंकाएँ थीं। हम यहाँ कुछ ऐसे लोगों की चर्चा भी सुन रहे थे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि त्रिभुवन सहकारी विधेयक, 2025 के शीर्षक और अंतर्वस्तु को लेकर जिस प्रकार की चर्चाएँ थीं और यहाँ पर जो चर्चाएँ हुई हैं, इसके पक्ष के अंदर जिन्होंने अपना वक्तव्य रखा है, उन्होंने मुझसे

पहले भी बहुत विस्तार से इस बात को रखा है कि किस प्रकार से यह बिल है, किस प्रकार से यूनिवर्सिटी काम करेगी और किस प्रकार से इसका नामकरण किया गया है। त्रिभुवन जी का उल्लेख मुझसे पूर्व के बहुत सारे विद्वान वक्ताओं ने किया है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार स्वतंत्रता सेनानी और भारत में सहकारी आंदोलन के जनक, त्रिभुवनदास किशिभाई पटेल के नाम के प्रति कृतज्ञता का भाव रखती है। महोदय, इस सभा के लिए यह भी बहुत गौरव की बात है कि त्रिभुवनदास किशिभाई पटेल 1967 से लेकर 1974 के बीच दो बार राज्य सभा के सदस्य रहे। उन्हें असाधारण समाज सेवा के लिए 1963 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1964 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया।

मान्यवर, 1855 में गठित ICA यानी कि International Cooperative Alliance का जो रिकॉर्ड है, वह यह दिखाता है कि भारत सहित 105 देश इसके सदस्य हैं, कुल 306 से अधिक सहकारी संगठन इसके सदस्य हैं और भारत से भी 18 संगठन इसके सदस्य हैं। इस संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यदि विश्व में कुल 30 लाख सहकारी समितियां हैं, तो उनमें 8,54,000 सहकारी समितियां अकेले भारत में हैं, जो दुनिया का लगभग 25 प्रतिशत आंकड़ा बैठता है। जब यह क्षेत्र इतना बड़ा है, तो फिर इस क्षेत्र को ठीक प्रकार से दिशा देने के काम में कहां दिक्कत आती है? इधर के हमारे विद्वान सदस्यों को किस बात से तकलीफ होती है? इस मंत्रालय के माध्यम से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना कर जो एक काम शुरू हुआ, चाहे हम FPO की बात करें या सहकारी बैंकों, PACS या अन्य ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे बैंकों का कंप्यूटरीकरण करने की बात हो, बड़ी खुशी की बात है कि PACS का कंप्यूटरीकरण करने के लिए 2,516 करोड़ रुपए का बजट भी अलॉट किया गया और यह टारगेट रखा गया कि प्रशिक्षित युवा आगे आएँ। जब इस प्रकार का टारगेट सेट किया गया, जब इस प्रकार के काम को करने का लक्ष्य सामने रखा गया, तो फिर यह जरूरी भी हो जाता है कि इस प्रकार के काम के लिए प्रशिक्षण के लिए, कोई ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, जहां से युवा निकल कर के आएँ और पूरी दुनिया में जिस प्रकार से कोऑपरेटिव का काम चल रहा है, उससे भी आगे बढ़कर के देश में कोऑपरेटिव क्षेत्र को मजबूत करने का काम करें। हमारी सरकार की प्राथमिकता policy paralysis को दूर करना है, इसलिए इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इधर के साथियों को इसका स्वागत करना चाहिए।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस विषय में आगे बताना चाहूंगा कि अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें, तो ICA, यानी International Cooperative Alliance के चार क्षेत्रीय कार्यालयों में से एक कार्यालय भारतवर्ष के अंदर है, जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। World Cooperative Monitor Report, 2023 के अनुसार भारत की सहकारी संस्था IFCO विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर आई है, अमूल को दूसरा स्थान मिला है और कृभको छठे स्थान पर रही है। यह सरकार जिस प्रकार से हमारे प्रधान मंत्री जी की दूरदृष्टि के विजन के आधार पर चलती है और हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विभाग आगे बढ़ रहा है, उससे मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो आंकड़े आज हम लोगों को दिखाई देते हैं, इस प्रकार के हमारे तीन बड़े संस्थान दुनिया के अंदर पहले तीन स्थान बनाए हुए हैं। अगर इसी गति से हम

लोग आगे लगे रहें, तो निश्चित रूप से हमारे और ज्यादा संस्थान दुनिया के 10 नंबरों के अंदर अपना स्थान अंकित करेंगे।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए हाउस से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण बिल, जो त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम इसको पास करें और हमारे ग्रामीण क्षेत्र को, हमारे सहकार के क्षेत्र को दुनिया के अंदर और आगे लेकर के जाएं। आपने मुझे जो समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): श्री नरेश बंसल।

श्री नरेश बंसल (उत्तराखंड)**:** उपसभाध्यक्ष जी, आज बड़ा महत्वपूर्ण बिल, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के स्थापित होने के बारे में आया है। मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं बैंक में नौकरी करता था। जब मैं उसको छोड़कर राजनीति में आया, तो मुझे सबसे पहला काम सहकारिता प्रकोष्ठ का मिला।

मैंने उसके प्रदेश महामंत्री के रूप में राजनीति में काम प्रारंभ किया और यहाँ तक पहुंचा हूँ। सहकारिता से मेरा विशेष लगाव भी है और सहकारिता हमारी संस्कृति का एक अंग है। भारत जब विश्व गुरु था, संपन्न था, तब भी सहकारिता से सब काम होते थे। मैं तो ध्यान देता हूँ, तो पाता हूँ कि जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए 'राम सेतु' का निर्माण किया, तो वह सेतु भी सहकारिता के आधार पर बना। द्वापर में श्रीकृष्ण भगवान ने सब ग्वालों को साथ में लेकर गोवर्धन उठाया, तो वह सहकारिता का रूप है। युगानुकूल परिवर्तन हमारी संस्कृति का अंग है। चूँकि 2047 में हमने वह वैभव प्राप्त करना है, जो हमारा पुराना वैभव था, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होना है, इसलिए उसकी तैयारी के लिए जो-जो चीजें चाहिए, वे सब हम कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता के आधार पर देश की आर्थिक स्थिति बदलेगी, ग्रामीण भारत का आर्थिक उन्नयन होगा, अंत्योदय का विकास होगा, अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि मिलेगी। उसके लिए, उसके प्रबंधन के लिए ऐसे युवकों, ऐसी बेटियों और महिलाओं की आवश्यकता होगी, जो उसके प्रबंधन में योगदान दे सके। आणंद में 'इरमा' के नाम से रूरल मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट पहले से था, उस मैनेजमेंट स्कूल से जो बच्चे पढ़ कर निकलते हैं, उनका उस क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में कोऑपरेटिव में बड़ा योगदान है। अमूल को भी वहाँ से निकले हुए बहुत सारे युवक मिले, जिन्होंने अमूल के विकास में योगदान दिया। अब उसको और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, जैसी विश्व स्तर पर स्थिति है, विश्व स्तर पर चुनौतियाँ हैं, उनका सामना करने के लिए और अधिक ज्ञान-संपन्न तथा और अधिक कैपेसिटी बिल्डिंग के हिसाब से हमारे छात्र-छात्राएँ हों - इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर 'त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय' की स्थापना हुई। अभी मेरे से पहले के वक्ताओं ने बताया कि यह कोऑपरेटिव सेक्टर का पहला विश्वविद्यालय बन रहा है। यह न कोई सरकारी यूनिवर्सिटी है, न कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बल्कि यह सहकारी विश्वविद्यालय है और सहकारिता के क्षेत्र के लिए है। इसका

उद्देश्य ही है सहकारिता आधारित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, छात्रों को उद्यमशीलता और आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना, शोध और सदाचार को सहयोगित करना। इस प्रकार से इसका उद्देश्य सहयोग और नवाचार को सहयोगित करना है।

उपसभाध्यक्ष जी, इस विश्वविद्यालय में सहकारी प्रबंधन, कृषि, वित्त और ग्रामीण विकास से जुड़े पाठ्यक्रम होंगे। इन सारे पाठ्यक्रमों से प्रशिक्षित होकर जो युवा निकलेंगे, उनको एक अच्छे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और सहकारिता के क्षेत्र में एक पारदर्शी प्रबंधन होगा, एक मितव्ययी प्रबंधन होगा, जिससे सहकारिता के क्षेत्र से सहकार से समृद्धि का जो हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी का संकल्प है, वह सपना भी पूरा होगा। हमें सहकार से समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए प्रशिक्षित होना आवश्यक है। यह विश्वविद्यालय व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा को सहकारी दृष्टिकोण से जोड़ेगा, डिजिटल शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा, सहकारी संस्थाओं के साथ जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, व्यवहारिक प्रशिक्षण है, वह भी अनिवार्य रूप से होगा।

इसका व्यापक प्रभाव राष्ट्र और सामाजिक जीवन पर पड़ने वाला है। इससे भारत में सहकारी आंदोलन को और मजबूती मिलेगी। अभी तक सामान्य रूप से यह माना जाता है कि सहकारिता का आंदोलन महाराष्ट्र और गुजरात में ज्यादा फला-फूला है। लोग मानते हैं कि सहकारी बैंक, शुगर मिल ज्यादातर इन्हीं दो राज्यों में हैं, लेकिन आज यह व्यापक रूप से पूरे देश में फैला है। चाहे टेक्सटाइल हो, जन औषधि केंद्र हों, सामान्य सुविधा केंद्र हों, पेट्रोल पंप हों, सीएनजी पंप हों, फर्टिलाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो 60,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से यह पूरे देश में हो रहा है। अब उसके साथ इतनी चीजें और जुड़ गई हैं कि विभिन्न बहुउद्देशीय मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बन रही हैं। इस प्रकार, अब इसका क्षेत्र व्यापक हो रहा है। इस व्यापक क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता है और यह यूनिवर्सिटी इस उद्देश्य को भी पूरा करेगी। इससे भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूती मिलेगी, ग्रामीण युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान में सहकारी शिक्षा अपना योगदान देगी और कृषि, दुग्ध उत्पादन, कुटीर उद्योग आदि में नवाचार और सतत् विकास होगा।

उपसभापति जी, मैं उत्तराखंड से आता हूँ। जहाँ तक इसमें महिलाओं के योगदान की बात है, तो देश भर में एक करोड़ लखपति दीदी बनी हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एक प्रकार से सहकारिता का ही काम है, क्योंकि उसमें 10-11 महिलाएँ एक ग्रुप बनाती हैं, वह छोटी सोसाइटी होती है, जो गांव में होती है और छोटा कारोबार करती है। उनमें से कोई अचार बनाने का काम करती है, कोई मुरब्बा बनाने का काम करती है, कोई कढ़ाई का काम करती है और कोई बुनाई का काम करती है। मैं अनेक रोज़गार मेलों में जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि उससे हमारी माताएँ-बहनें किस प्रकार से लाखों रुपए साल कमा रही हैं। सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक-दूसरे से समन्वय करते हुए कोऑपरेटिव बैंक्स भी उसमें उनको ऋण देते हैं। 5 लाख रुपये तक का ऋण आज ज़ीरो परसेंट पर उनको मिल रहा है, जिससे उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरे क्षेत्र में मिलेट्स होता है, तो वहाँ मिलेट्स की कुकीज़ बनाने की फैक्ट्री अभी लगी है। कोऑपरेटिव सेक्टर में एलईडी के बल्ब बन रहे हैं, शॉल बन रहे हैं। इस प्रकार से ये चीजें निरंतर आगे बढ़ रही हैं। यह

सहकारी विश्वविद्यालय एक प्रकार से सहकारिता आंदोलन, सरकार का जो सहकार से समृद्धि का लक्ष्य है, उसको आगे बढ़ाने के लिए चल रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सहकारी क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा।

पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के दौरान, वित्त वर्ष 2013-14 में सहकारी संस्थाओं के लिए बजट का आवंटन 122 करोड़ रुपये था, जिसके कारण ग्रामीण कारीगरों के लिए आवश्यक कार्यक्रमों को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल सकी और महाराष्ट्र में 101 सहकारी चीनी मिलें बंद हो गईं। इसके विपरीत, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री, मोदी जी जब से आए हैं, तब से उन्होंने सहकारिता, जो पहले कृषि मंत्रालय का एक भाग होता था, उसको अलग सहकारिता मंत्रालय बनाकर उस पर विशेष ध्यान दिया है और हमारे अमित भाई इसके मंत्री बने हैं। उन्होंने वर्ष 2021 में स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की और इस क्षेत्र के लिए बजट 1,183.39 करोड़ कर दिया, जो यूपीए सरकार के बजट से 9.7 गुना ज्यादा है।

इसके अलावा, डेयरी सहकारी योजना के अंतर्गत डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों के आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण के लिए पांच हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो यूपीए सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी योजना में आवंटित राशि का दोगुना है। यह महत्वाकांक्षी विधेयक सरकार के सहकारी ढांचे को मजबूत कर हाशिये पर मौजूद समुदायों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आत्मनिर्भर भारत के लिए विशिष्ट शिक्षा को मज़बूत करना मोदी सरकार का लक्ष्य है। मुख्य क्षेत्रों के लिए विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना करके भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य को सक्रिय रूप से परिवर्तित किया जा रहा है। उपसभाध्यक्ष जी, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, जिसे आईआरएमए से विकसित किया जाएगा, सहकारी क्षेत्र की शिक्षा पर केंद्रित होगा और "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करेगा। ठीक उसी प्रकार, जैसे आईआरएमए लम्बे समय से अमूल जैसी भारत की प्रमुख सहकारी संस्थाओं को प्रतिभा प्रदान कर रहा है।

मैंने पहले भी कहा है कि जिस प्रकार आणंद का रूरल मैनेजमेंट संस्थान युवाओं को प्रशिक्षित कर रहा है और अमूल को उसका बड़ा लाभ मिल रहा है, उसी प्रकार इस विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद देश-विदेश के छात्र भी पढ़ने के लिए आएंगे। उनके प्रशिक्षण से प्रशिक्षित युवक-युवतियाँ पूरे देशभर में विदेशी संवाद स्थापित करेंगे और सहकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस विश्वविद्यालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

जिस तरह गतिशक्ति विश्वविद्यालय परिवहन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में विशेषज्ञता को बढ़ावा दे रहा है और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आंतरिक सुरक्षा व पुलिसिंग के अध्ययन का केंद्र बना हुआ है, उसी प्रकार लद्दाख में स्थित सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय जलवायु विज्ञान, ऊर्जा और लोक नीति में अनुसंधान को आगे बढ़ा रहा है। यह विश्वविद्यालय क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक चुनौतियों का समाधान करने में सहायक है। हर क्षेत्र की अपनी अलग-अलग चुनौतियाँ होती हैं और विश्वविद्यालयों की यही भूमिका होती है कि वे छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के समाधान के लिए तैयार करें।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहकारिता के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को संबोधित करेगा और युवक-युवतियों को सहायता प्रदान करेगा। यह संस्थान केवल एक शैक्षणिक केंद्र ही नहीं होगा, बल्कि रोजगार सृजन का भी प्रमुख स्रोत बनेगा। यह छात्रों को विशिष्ट कौशल प्रदान कर उन्हें भारत के आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में सीधे योगदान के लिए तैयार करेगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले रोज़गार के अवसर सृजित होंगे और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित होगा।

सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय नीतिगत कार्रवाई करते हुए मोदी सरकार ने हमेशा विधायी और नीतिगत कार्रवाई आधारित शासन का समर्थन किया है। सरकार की यह दूरदृष्टि सहकारी क्षेत्र में भी परिलक्षित होती है। वर्ष 2023 में मोदी सरकार ने बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं में प्रशासन को सशक्त बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना, जवाबदेही सुनिश्चित करना और चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाना था।

वर्तमान विधेयक के माध्यम से मोदी सरकार देश में सहकारी आंदोलन को संस्थानों के एक नेटवर्क के माध्यम से मजबूत करने का प्रयास कर रही है। प्रस्तावित सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ सहकारी क्षेत्र में कुशल कार्यबल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। क्षमता निर्माण पर इस विशेष ध्यान से न केवल तकनीकी दक्षता में वृद्धि होगी, बल्कि यह हाशिये पर मौजूद वर्गों को सशक्त बनाते हुए सहकारी शासन में अधिक भागीदारी के अवसर भी प्रदान करेगा। ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**)**:** धन्यवाद। आप समाप्त करें।

श्री नरेश बंसलः महोदय, मैं बस तीस सेकंड में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन के निवेश के माध्यम से सहकारी समितियों का क्षमता निर्माण वित्त वर्ष 2024-25 के केन्द्रीय बजट में भारत की संपदा का ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री नरेश बंसलः भारत की संपदा का लाभ उठाने और अमृत पीढ़ी को सक्षम बनाकर विकसित भारत, 2047 की मजबूत नींव रखने का प्रयास इसके माध्यम से होगा। अंत में मैं केवल यही निवेदन करता हूं कि जिस सद्भावना और सहकार से समृद्धि और अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए बिल लाया गया है, इसका सब लोग स्वागत करें और समर्थन करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Next speaker is Shri Ravi Chandra Vaddiraju. Hon. Member will speak in Telugu. You have five minutes.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.)

SHRI RAVI CHANDRA VADDIRAJU (Telangana): *“ Hon. Deputy Chairman, thank you for allowing me to speak on the "Tribhuvan" Sahkari University Bill, 2025. Education, research, and skill development are essential to strengthening the cooperative sector, and I support this Bill introduced by the Central Government. I believe the allocation of Rs. 1,122 crore for this Bill will significantly contribute to the development of the cooperative sector. Allocating Rs. 500 crore to the university and aiming to train 8 lakh people each year through 284 cooperative training centers are promising steps. Additionally, the allocation of Rs. 600 crore for the digitization and modernization of Primary Agricultural Credit Societies (PACS), start-ups, and the establishment of innovation centers in the cooperative sector is a commendable decision. However, I am concerned about the insufficient priority given to Telangana in this Bill. Currently, we have only one cooperative training center in Hyderabad, making it challenging to provide adequate training to cooperatives at the district level. It is essential to expand training centers to areas like Adilabad, Nizamabad, and Khammam.

While schemes such as Rythu Bandhu, Rythu Bima, and the Dharani Portal support the cooperative system in Telangana, it remains unclear how much our State has genuinely benefited from these Central Government initiatives. We must ensure that funds provided by NABARD and NCDC to cooperative societies are adequately distributed to our State. Moreover, priority should be given to Telangana while allocating funds to women's self-help groups. Primary Agricultural Credit Societies (PACS) and dairy cooperatives in Telangana require modernization. I propose that special funds be established to support new cooperative start-ups in the State. Additionally, adequate representation for the States should be ensured in the governing bodies of the cooperative sector. If appropriate changes are made to this Bill, we can further strengthen the cooperative sector. Therefore, the Central Government should consider the views of the States while drafting the Bill.

With the Indira Kranthi Patham (IKPs), milk dairies, women's self-help groups, and the expansion of procurement centers from 6,000 to 9,000, Shri KCR has turned Telangana into a "Golden Telangana." The Government has purchased crops, including corn and rice, to benefit the farmers of Telangana. We request the establishment of a university in Telangana and a Millet Research Centre in

* English translation of the original speech delivered in Telugu.

Rajendranagar, especially since this year has been declared the International Year of Millets. I suggest introducing a course on millets.

The incumbent Congress Government in Telangana plans to sell 400 acres of valuable land located at the Hyderabad Central University. Instead of selling this land, it could be used to establish a new university. It is the responsibility of all of us, particularly the Central Government, to safeguard this land.

Shri KCR has built nearly 2,600 Rythu Vedika centers across Telangana, with one center established for every 5,000 acres of land. Farmers used these centers to discuss issues related to farming. There are nearly 900 PACS in Telangana, which have played a critical role in disbursing loans to farmers. Shri KCR has also significantly contributed to the development of fisheries in Telangana by providing free fish and rehabilitating rivers and canals for the benefit of fishermen.

Telangana is a leading state in inland fisheries, and cooperative societies in the region have been digitized and modernized under the leadership of Shri KCR. The weavers' society has also been strengthened, leading to large-scale employment opportunities.

The establishment of additional cooperatives can strengthen the country's economy, and Telangana serves as a prime example of this. Farmer Producer Organizations (FPOs) have been established in Telangana; however, farmers are advocating for an increase in the number of FPOs in the State. If cooperatives are managed with an agricultural approach, input costs will be reduced. I support this Bill and reiterate that the responsibility of protecting the valuable land at Hyderabad Central University lies with all of us, particularly the Central Government. Thank you, Sir."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, hon. Minister, Shri Murlidhar Mohol, to reply to the discussion.

श्री मुरलीधर मोहोल: उपसभापति महोदय, आज सदन में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के विषय पर चर्चा हो रही है। सदन में, इस चर्चा में पिछले लगभग चार, साढ़े चार घंटे तक, लगभग 28 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। महोदय, सबसे पहले तो सदन के ज्येष्ठ सदस्य माननीय दिग्विजय सिंह जी ने इसकी शुरुआत की और अभी आखिरी सदस्य के रूप में माननीय रविचंद्र वद्दीराजू जी ने यहाँ पर अपने विचार रखे। माननीय उपसभापति महोदय, मैंने सदन में सभी माननीय सांसदों के भाषण सुने हैं। इस विषय पर यहाँ अनेक सदस्यों ने अपने सुझाव भी दिए हैं और मैं उन सुझावों का स्वागत करता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने राजनीतिक टीका-

टिप्पणी भी की है, लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि सदन में जो चर्चा हुई है, उस चर्चा को सभी माननीय सदस्यों के माध्यम से समृद्ध किया गया है।

मोदी जी और देश के गृह एवं हमारे सहकारिता मंत्री माननीय अमितभाई शाह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के ऐतिहासिक निर्णय पर आज इस सदन में जो चर्चा चल रही है, उन्होंने मुझे उसका हिस्सा बनने का अवसर दिया है।

माननीय उपसभापति महोदय, मुझे इस सदन में सभी को यह बात बताते हुए बहुत गर्व है कि दिल्ली में नवंबर, 2024 में एक वैश्विक सहकारी सम्मेलन संपन्न हुआ था। भारत में यह सम्मेलन पहली बार हुआ था, जिसमें पूरे विश्व से 106 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उस सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन्स द्वारा हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारे सहकारिता मंत्री माननीय अमितभाई शाह जी की उपस्थिति में वर्ष 2025 को 'अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष' घोषित किया गया है। यह हमारे देश और देश की सहकारिता का सम्मान है और हम सबके लिए गौरव का विषय है। महोदय, आज, जब हम यह अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 मना रहे हैं, तो उसी दौरान, आज सदन में देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना पर चल रही चर्चा में भाग भी ले रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, जब माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है, तब इस लक्ष्य को पूरा करने में देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। आज देश की लगभग 50 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अगर हम सहकारिता क्षेत्र को देखें, तो आज देश में लगभग 8 लाख सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं और इन संस्थाओं की सदस्य संख्या 30 करोड़ है। आज 30 करोड़ सदस्य इस पूरे देश के सहकारिता क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हर किसान परिवार का कोई न कोई एक सदस्य इस सहकारिता क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इतने बड़े लोकसंख्या से जुड़े सहकारी क्षेत्र को पिछले कई सालों से कांग्रेस की सरकारों ने कैसे नजर अंदाज किया है, इसके मैं केवल दो उदाहरण यहां देना चाहूंगा। हमारे सीनियर माननीय सदस्य श्री दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि पिछले 10 सालों में सहकारिता के लिए आपने क्या किया। यह भी मैं बताने वाला हूं और मैं इस पर अभी आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर हम 2013-14 का सहकारी विभाग का बजट देखें - तब हमारा यह विभाग कृषि मंत्रालय के अंतर्गत था – वह सिर्फ 122 करोड़ रुपए था। अगर आज हम मोदी जी की सरकार में देखें, तो इसमें करीब 10 गुना वृद्धि होकर हमारा बजट लगभग 1,190 करोड़ रुपये है। इससे यह मालूम होता है कि हमने सहकारिता को कितना महत्व दिया है। इतना ही नहीं, 30 करोड़ से अधिक सदस्यता वाली इन सहकारी समितियों को पहले केंद्रीय कृषि मंत्रालय के तहत वर्षों से चलाया जा रहा था और इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी केवल एक संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी पूरे देश की सहकारिता चला रहे थे, लेकिन माननीय उपसभापति महोदय, इससे ध्यान में आता है कि सालों से यह सहकारिता क्षेत्र कांग्रेस की सरकारों के समय में दुर्लक्षित रहा।

माननीय उपसभापति महोदय, जैसे कि हमारे सर्वोच्च नेता माननीय मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने कई अच्छे काम हमें करने के लिए छोड़े हैं, जैसे कि राम मंदिर का निर्माण, कश्मीर से धारा 370 को हटाना, ट्रिपल तलाक पर रोक लगाने का कानून, ऐसे ही कई काम गिनाए जा सकते हैं और वैसा ही एक और ऐतिहासिक निर्णय जो देश के करोड़ों किसान परिवारों के कल्याण के लिए लिया गया, वह था स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना करना। आज हम देखते हैं कि पूरे देश में चाहे वह PACS हो, डेयरी हो, शुगर इंडस्ट्री हो, कोऑपरेटिव बैंक्स हों, टेक्सटाइल मिल्स हों, ऐसी लाखों सहकारी समितियां काम कर रही हैं। उनके विकास और विस्तार के लिए और इस सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा जुलाई, 2021 में इस स्वतंत्र मंत्रालय को गठित किया गया और एक दूरदर्शी निर्णय लिया गया।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को कुछ तथ्य भी बताना चाहूंगा, जो मुझे लगता है कि कम लोग जानते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व, जिसने अपने गांव के PACS में भी काम किया, जिसने अपनी बाजार समिति में भी काम किया, वे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी थे, वे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के संचालक डायरेक्टर भी बने, जिनका सहकारिता क्षेत्र में बड़ा योगदान और अनुभव रहा, ऐसे हमारे नेता माननीय अमित भाई शाह देश के पहले सहकारिता मंत्री बने। यह हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। उन्हीं के नेतृत्व में जुलाई, 2021 से अब तक सिर्फ साढ़े साल में सहकारिता मंत्रालय द्वारा अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं, जिन पर मैं अभी आने वाला हूं। बहुत सारे सदस्यों ने पूछा कि 10 साल में क्या किया?

माननीय उपसभापति महोदय, आज हम यह बिल लेकर आए हैं, लेकिन सहकारिता विश्वविद्यालय की आवश्यकता क्यों है, इस बिल को इस समय लाने की क्या जरूरत है, तो मुझे विस्तार से सदन के सामने इस विषय को रखना है। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने देश में 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना रखी और उसे साकार करने के लिए पिछले साढ़े तीन साल में हमारे सहकारिता मंत्रालय ने कितने काम किए, मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देश के सामने रखना चाहता हूँ। माननीय अमित भाई के कुशल नेतृत्व में हमारे मंत्रालय ने भविष्य में इस देश के सहकारिता क्षेत्रों को नई दिशा देने के लिए 60 नई initiatives लीं। इसमें सबसे पहले हमारे मंत्रालय ने जो सबसे बड़ा कार्य शुरू किया, जिस पर इस सदन में बहुत चर्चा हुई, वह है हमारी PACS. हमने जो सबसे पहला काम हाथ में लिया, वह था PACS का सशक्तीकरण। माननीय उपसभापति महोदय, PACS हमारे सहकारिता क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। PACS गाँव को सहकारिता से जोड़ने का एक प्रमुख केंद्र है और यह प्रमुख कार्य करती है। यहाँ बहुत सारे अनुभवी सभासद हैं, जिन्होंने सहकारिता पर भाषण भी किया, उसमें उन्होंने बताया कि PACS के माध्यम से पहले केवल छोटे-छोटे काम होते थे। जैसे short term crop loan हो या input supply का काम हो, बस इतना ही काम PACS के माध्यम से होता था। इसी वजह से उनके व्यवसाय पर मर्यादा आती थी। लेकिन माननीय उपसभापति महोदय, इसी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और इसके समाधान के लिए PACS के model bye-laws में सुधार किए गए और इसके माध्यम से हमने PACS को multi-purpose बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। माननीय अमित भाई ने हर राज्य के मुख्यमंत्री से चर्चा की, पत्र व्यवहार किया और मुझे यहाँ यह कहने में बड़ी खुशी होती है

कि हमने PACS को multi-purpose बनाने के लिए जो model bye-laws बनाए, पूरे देश में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसको adopt किया। उस राज्य में किसी भी विचारधारा की सरकार हो, लेकिन सभी ने इसको सकारात्मक प्रतिसाद दिया। मैं यहाँ पर उन सभी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ।

माननीय उपसभापति महोदय, PACS के बहुउद्देश्यीय होने से अब उनके माध्यम से Common Service Centres भी चल रहे हैं, पेट्रोल और एलपीजी डीलरशिप भी PACS को मिल रही है, Custom Hiring Centres भी PACS के माध्यम से चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चल रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र PACS के माध्यम से चल रहे हैं, ग्रामीण नल जल पूर्ति योजना के प्रबंधन का काम भी हमारी PACS कर रही हैं। ऐसे 25 नए व्यवसाय इन PACS को देने का काम हमारी सरकार ने किया। माननीय उपसभापति महोदय, उदाहरणस्वरूप मैं यहाँ पर यह बात रखना चाहूँगा कि आज देश में हमारी 43 हजार PACS Common Service Centres चला रही हैं। आज हमारी 36 हजार PACS प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र चला रही हैं। हमारी 4 हजार PACS प्रधानमंत्री जन औषधालय चला रही हैं। देश में अनेक PACS हैं, जो पेट्रोल पंप भी चला रही हैं। ऐसे बहुत सारे काम PACS के माध्यम से आज देश भर में शुरू हैं।

इसी तरह से जब PACS आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, तभी तो उस गाँव के किसान का परिवार भी सशक्त होगा, वह गाँव भी समृद्ध होगा और यही हमारी कल्पना है, यही माननीय मोदी जी की कल्पना है। अगर हम 'सहकार से समृद्धि' के बारे में बोलें, तो हमारे यहाँ गाँवों में इन PACS के माध्यम से जो काम चल रहा है, पहले हमें उसे अच्छा करना था, मुझे इस सदन में यह कहते हुए बड़ा आनंद होता है। इन्हीं PACS के कार्य में सुलभता लाने के लिए भारत सरकार द्वारा, हमारे मंत्रालय द्वारा अभी देश भर में लगभग 67 हजार PACS का computerization किया जा रहा है। उसका मुद्दा भी यहाँ चर्चा में आया था कि कौन से राज्य में कितना किया जा रहा है, हमारे राज्य में कितना किया जा रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज देश की 67 हजार PACS computerize की जा रही हैं और उसके लिए 2,516 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

माननीय उपसभापति महोदय, यहाँ पर बार-बार चर्चा हुई कि 'सहकारिता' राज्य का विषय है। हाँ, यह राज्य का विषय है, लेकिन राज्य की सहकारिता को सशक्त बनाने के लिए, उनको ताकत देने के लिए हमने आज ऐसे काम हाथ में लिए हैं। मुझे यह कहने में बड़ा आनंद होता है कि यह राज्य का विषय है, PACS राज्य की हैं ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat. Let him reply. ...*(Interruptions)*... No, please take your seat. ...*(Interruptions)*...

श्री मुरलीधर मोहोल: यह राज्य का विषय है, लेकिन हमारी सरकार ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please take your seat. ...*(Interruptions)*...

श्री मुरलीधर मोहोलः हमारी सरकार PACS के सशक्तिकरण के लिए आज इतना कुछ काम कर रही है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... शान्त रहिए। कृपया आपस में बात नहीं करें।

श्री मुरलीधर मोहोलः माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह भी अवगत करना चाहता हूँ कि देश में अभी भी कई पंचायतें ऐसी हैं कि जहाँ पर कोई सहकारी संस्था नहीं है, अभी वहाँ काम नहीं कर रही है। हमारी सरकार का प्रयास यह है कि देश का हर गांव सहकारिता के माध्यम से समृद्ध हो। इसके लिए हमारे मंत्रालय ने आने वाले 5 सालों में 2 लाख नए PACS बनाने का लक्ष्य रखा है। महोदय, उनमें से 14,000 PACS बन भी चुके हैं। इसमें बड़ी बात यह देखिए कि सहकारिता पर जिन्होंने बात की, अपनी बातें रखीं और बोले कि सहकारिता कांग्रेस ने की, लेकिन पिछले कई सालों से PACS की संख्या 1 लाख से ऊपर नहीं गई, अब अगले 5 सालों में पूरे देश में PACS की संख्या 3 लाख तक जाएगी। यह सहकारिता को देखने का हमारा दृष्टिकोण है। मुझे लगता है कि अगर ये PACS बनेंगे, तो पूरे देश में सहकारिता के क्षेत्र में वह एक नयी क्रांति होगी।

माननीय उपसभापति महोदय, हमारी सरकार ने PACS को बहुउद्देश्यीय बनाने के साथ-साथ, NDDB के माध्यम से dairy और NFDB के माध्यम से fisheries को भी बढ़ावा देने का काम किया। जब हम नए PACS बना रहे हैं, तो उनमें देश की सामाजिक रचना को भी ध्यान में रखा गया है। वह कैसे, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गों और महिलाओं को सहकारी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने का निर्णय किया है। अब हमारी सरकार ने by-laws के तहत PACS के board of directors में एक SC-ST वर्ग का सदस्य और एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य किया है और सहकारिता के क्षेत्र में हम लोग इसी के माध्यम से सामाजिक न्याय देने का काम भी कर रहे हैं।

माननीय उपसभापति महोदय, वर्तमान में पूरे देश के सहकारिता क्षेत्र की स्थिति जानने के लिए और भविष्य की दिशा तय करने के लिए, हम सभी राज्य सरकारों को साथ में लेकर काम कर रहे हैं। मैं बार-बार यह शब्द इसीलिए प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार यह सुनने को आया कि राज्य का विषय है, राज्य का विषय है, लेकिन हम राज्यों को साथ में लेकर काम करते हैं। हमने सभी राज्यों को साथ में लेकर पूरे देश का एक National Cooperative Database तैयार किया है। आज हमें केवल एक click पर, केवल एक मिनट में, राज्य, जिला, तहसील और गांव सभी स्तरों पर कार्य करने वाली हमारी सहकारी संस्थाओं की जानकारी मिलती है। 8 लाख के ऊपर हमारी सहकारी संस्थाएँ हैं। यह काम हमने सभी राज्यों को साथ में लेकर अभी किया है। मैं सभी माननीय सदस्यों का भी आह्वान करना चाहता हूँ कि इस Database का उपयोग करके हम सभी अपने क्षेत्रों में सहकारिता को मजबूत करने में भी अपना-अपना योगदान दे सकते हैं।

माननीय उपसभापति महोदय, 2002 के बाद पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और अमित भाई जी के नेतृत्व में हमारे देश की राष्ट्रीय सहकारिता

नीति भी बनाई जा रही है। कुछ दिन में वह भी सभी को दिखेगी। देश भर में राष्ट्रीय सहकारिता नीति लाने का हमारा एक संकल्प है।

माननीय उपसभापति महोदय, 2023 में देश में पहली बार माननीय अमित भाई के नेतृत्व में हमने देश के किसानों को बीज से बाजार तक सुविधा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तीन नई सहकारी समितियां बनाईं। उनमें पहली BBSSL, दूसरी NCOL और तीसरी NCEL हैं। महोदय, हमारे देश में जो पारंपरिक और मीठे बीज हैं, उनके संवर्धन और प्रसार का काम भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के माध्यम से अभी शुरू हो गया है। देश में जैविक उत्पादन की खेती को National Co-operative Organics Limited के माध्यम से बढ़ावा देने का काम शुरू किया गया है। हमारे किसानों के कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए National Cooperative Exports Limited द्वारा अब किसानों को विदेशी बाजारों से जोड़ा जा रहा है। महोदय, ये जो तीन हमारी राष्ट्रीय सहकारी समितियां हैं, अब तक देश में 34,000 सहकारी संस्थाएं इनकी सदस्य बनी हैं और मुझे लगता है कि इससे अब किसानों के आय में भी बिल्कुल वृद्धि होगी।

माननीय उपसभापति महोदय, आज देश भर में लगभग 1,450 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जिनका देश के शहरी क्षेत्रों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। हम सब जानते हैं कि नाबार्ड के माध्यम से हमारे जिला कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को मदद की जाती है, उनकी सहायता की जाती है। लेकिन आज हमारे देश में इतनी बड़ी संख्या में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए आज तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आज मुझे सदन में यह कहते हुए बहुत आनंद और अभिमान महसूस हो रहा है कि माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय अमित शाह जी की दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समन्वय करके अंब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है।

माननीय उपसभापति महोदय, अब इससे क्या होगा? जैसे मैंने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वह स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो या जिला कोऑपरेटिव बैंक हो, उनके लिए नाबार्ड तो है और अगर उनको कहीं पर दिक्कतें आती हैं, समस्याएँ आती हैं, तो वे उनके लिए खड़ी रहती हैं। अब हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इस अंब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आईटी सर्विसेज़ दे सकते हैं, टेक्निकल इन्फ्रास्ट्रक्टर के लिए मदद दे सकते हैं और आवश्यक आर्थिक सहायता भी दे सकते हैं। इस वजह से अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी शेड्यूल बैंक्स की तरह सेवाएँ प्रदान कर पाएँगे।

माननीय उपसभापति महोदय, हमारे मंत्रालय ने किसानों के कल्याण के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हम सबको इस बात का गर्व है कि हमारे देश के किसानों की मेहनत की वजह से आज हमारा देश कृषि उत्पादन में अग्रणी देशों में गिना जा रहा है। परंतु, फिर वही एक दुख की बात यह है कि इतने सालों से यह किसी के ध्यान में नहीं आया। इस मामले में पिछली सरकारों की लापरवाही थी। उन्होंने उसको दुर्लक्ष्य किया, जिसकी वजह से अनाज उत्पादन के क्षेत्र में भंडारण की क्षमता नहीं बनाई गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारे सहकारिता मंत्रालय ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। आज पूरे देश में पैक्स के माध्यम से अन्न भंडारण योजना का काम शुरू हो गया है। इसके कारण अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी

आएगी, फसल की सुरक्षा होगी और किसानों को नजदीक में भंडारण की सुविधा भी मिलेगी एवं इससे किसान को आर्थिक रूप से अधिक लाभ भी होगा।

माननीय उपसभापति महोदय, एनसीडीसी सहकारिता क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए कार्य करने वाली एक प्रमुख संस्था है। एनसीडीसी के माध्यम से पूरे देश में सहकारिता क्षेत्र को एक आर्थिक सहायता के स्वरूप में मदद की जाती है, एक आधार दिया जाता है। मैं फिर उसी मुद्दे पर आना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में हमने क्या किया? अगर हम कांग्रेस की सरकार के समय में देखें और 2013-14 के आंकड़े देखें, तो 2013-14 में एनसीडीसी के माध्यम से देश की सहकारी संस्था को सिर्फ 5,300 करोड़ रुपए की मदद की गई। माननीय उपसभापति महोदय, वहीं आज हमारे नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने उसमें 25 गुना वृद्धि की और आज हमने 1,28,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता को एनसीडीसी के माध्यम से मंजूरी दे दी है। केवल इसी एक वर्ष में एनसीडीसी ने देश की चीनी मिलों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की है। माननीय अमित शाह जी के प्रयासों से कई सालों से लंबित चीनी मिलों की लगभग 46,000 करोड़ रुपए की income tax liability को भी माफी मिली है और इसका सीधा फायदा आज हमारे किसानों को मिला है। NCDC के माध्यम से और भी अनेक कार्य किये जा रहे हैं, जिससे आज देश की सहकारिता मजबूत हो रही है।

माननीय उपसभापति महोदय, सहकारिता को और मजबूत करने के लिए माननीय अमित शाह जी ने एक और परिकल्पना रखी। उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और उन्होंने 'सहकारिता में सहकार' की एक परिकल्पना लाई, यानी cooperation amongst cooperatives. इसमें हमने एक ऐसा निर्णय लिया कि यदि कोई जिला कोऑपरेटिव बैंक है, तो उस बैंक में उस जिले की सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और संस्थाएँ हों और उनका अकाउंट वहीं पर खोला जाएगा एवं उनके आर्थिक व्यवहार उन्हीं के माध्यम से होंगे।

8.00 **P.M**

उनके जो सदस्य हैं, उनके अकाउंट्स भी हमारे जिला कोऑपरेटिव बैंक में खोले जाएँगे। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यह निर्णय होने के बाद, अब तक देश के विभिन्न जिला सहकारी बैंकों की जमा राशि में कई गुना वृद्धि हुई है। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: अब आप यूनिवर्सिटी पर आइए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please wait, he will come. ...(*Interruptions*)... Please, please.

श्री मुरलीधर मोहोल: मैं अब उसी पर आता हूँ। इस यूनिवर्सिटी की जरूरत क्या है, इसका यह पहला अध्याय है। ...(**व्यवधान**)... आप सुनिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please.

श्री मुरलीधर मोहोल: माननीय उपसभापति महोदय, इसका उद्देश्य इतना ही है कि अगर हमारा जिला कोऑपरेटिव बैंक आर्थिक रूप से सक्षम होता है, तो हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी सक्षम होगा और उसका फायदा चाहे PACS के माध्यम से हो या किसी और सुविधा के माध्यम से हो, वह सीधे हमारे किसानों को होगा, इसीलिए मुझे लगता है कि इस परिकल्पना को आज पूरे देश में बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।

माननीय उपसभापति महोदय, आज देश में लगभग 1,730 Multi-State Cooperative Societies भी हैं, जिनमें सुधार के लिए हमारी सरकार ने 2023 में Multi-State Cooperative Societies Act में भी बदलाव किए। हमने कार्यक्षमता में वृद्धि और पारदर्शिता लाने के लिए इस एक्ट में बदलाव किए। हमारी सरकार ने Central Registrar के कार्यालय का भी कंप्यूटराइजेशन किया। मैं फिर यह कहता हूँ कि अब हम सरकार के माध्यम से राज्यों के RCS कार्यालयों का कंप्यूटराइजेशन भी कर रहे हैं। Multi-State Cooperative Societies को सुविधा प्रदान करने के लिए अब देश में CRCS के क्षेत्रीय कार्यालय भी अन्य राज्यों में खोले जाएंगे।

माननीय उपसभापति महोदय, मैंने अभी विस्तार से बताया कि कैसे देश का सहकारिता आंदोलन मजबूत हो रहा है, देश सहकार से समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। ...(**व्यवधान**)... इसमें गतिशीलता लाने और इसका विस्तार करने के लिए एक institutional व्यवस्था की जरूरत है। ...(**व्यवधान**)... मैं आया न!

श्री उपसभापति: कृपया आपस में बात न करें। माननीय मंत्री जी, आप बोलें।

श्री मुरलीधर मोहोल: माननीय उपसभापति महोदय, मुझे यही कहना था कि हम सहकारिता क्षेत्र में पिछले 10 साल में कितनी बड़ी क्रांति लाए और हमने कितना बड़ा काम किया है। अब इसे आगे ले जाने के लिए, इसे और बढ़ाने के लिए हमें एक institutional व्यवस्था की जरूरत है, इसीलिए हमने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की है।

माननीय उपसभापति महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वर्तमान में देश में 8 लाख से अधिक सहकारी समितियाँ काम कर रही हैं। इनमें लगभग 40 लाख कर्मचारी और 80 लाख निर्वाचित बोर्ड मेंबर्स काम कर रहे हैं। ऐसे कुल सवा करोड़ लोग आज इस सहकारिता से सीधे जुड़े हुए हैं। उनका समय-समय पर क्षमता निर्माण और कौशल विकास करना भी जरूरी है। इसके साथ ही, हमने अक्सर यह देखा है कि कार्यक्षमता में कमी होने के कारण कई सहकारी संस्थाओं की performance अच्छी नहीं होती, मैनेजमेंट में अनियमितता होती है और टेक्नोलॉजी का कम उपयोग होता है। ऐसी अनेक दिक्कतों का सामना आज हमारे देश की कोऑपरेटिव को करना पड़ रहा है।

माननीय उपसभापति महोदय, इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र का scale and scope भी निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। इससे नए उद्यम, स्वरोजगार और नवाचार के अवसर भी पैदा होंगे। आज PACS के सचिव से लेकर apex bank के MD तक सभी स्तरों पर

कार्य सुलभता और अनुशासन के लिए योग्य प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ऐसा अनुमान है कि आने वाले पाँच सालों में सहकारिता क्षेत्र को लगभग 17 लाख प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए हमने यह इनिशिएटिव लिया है। महोदय, वर्तमान में सहकारिता में हर स्तर पर शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और वह विखंडित भी है। इसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय अमित भाई के नेतृत्व में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का दूरदर्शी निर्णय हमारे मंत्रालय ने लिया और आने वाले समय में यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता क्षेत्र की प्रशिक्षित मैनपावर की आवश्यकता को निश्चित रूप से पूरा करेगा। यह विश्वविद्यालय देश के युवाओं में कोऑपरेटिव स्प्रिट की भावना को विकसित करेगा, सहकारी क्षेत्र में लॉन्ग टर्म करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस सदन में इस विश्वविद्यालय का नाम त्रिभुवन दास जी के नाम पर क्यों रखा गया, इस पर भी बोलना चाहता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हों या त्रिभुवन दास पटेल जी, यह हमारी संस्कृति है। हमारी पार्टी का विचार है कि कोई भी व्यक्ति, जिसने समाज की किसी भी व्यवस्था में बड़ा योगदान दिया है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। यह हमारी संस्कृति है। आज त्रिभुवन दास जी के नाम पर आक्षेप लिया गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वे कांग्रेस के ही थे। फिर भी, हम उनके कार्य और योगदान का सम्मान कर रहे हैं और इसे आपको स्वीकार करना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

स्वर्गीय त्रिभुवन दास जी स्वतंत्रता सेनानी भी थे और भारत में सहकारी आंदोलन के जनक माने जाते हैं। वे खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। ...(**व्यवधान**)... सहकारिता क्षेत्र में योगदान देते समय, त्रिभुवन दास जी ने गांधी जी और सरदार पटेल के मार्गदर्शन में कार्य किया। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्लीज़, आपस में बात न करें। Dr. John Brittas, please take your seat. *...(Interruptions)...* सिर्फ माननीय मंत्री जी का बात रिकॉर्ड पर जा रही है।

श्री मुरलीधर मोहोलः मैं फिर से यह बात दोहराना चाहता हूं। सहकारिता क्षेत्र में योगदान देते समय, त्रिभुवन दास जी ने गांधी जी और सरदार पटेल के मार्गदर्शन में कार्य किया। उनके नेतृत्व में देश के डेयरी क्षेत्र में क्रांति आई। उनकी नीतियों के कारण ही आज लगभग 60 हजार करोड़ रुपये का वार्षिक व्यापार करने वाला अमूल, विश्व स्तर पर प्रसिद्ध ब्रांड बन चुका है और इसका सीधा लाभ आज अमूल से जुड़े 36 लाख किसानों को मिल रहा है। ...(**व्यवधान**)... सहकारिता आंदोलन के ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम इस विश्वविद्यालय से जुड़ना अपने आप में गौरव की बात है।

माननीय उपसभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने श्री वर्गीज कुरियन जी के बारे में भी सदन में चर्चा की। इस विषय पर लोकसभा में माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी द्वारा उत्तर दिया गया था। ...(**व्यवधान**)... मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इसमें कोई दो

राय नहीं है कि कुरियन जी का सहकारिता क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। हम इसे स्वीकार भी करते हैं।

गुजरात राज्य में – आज आप कुरियन जी का नाम ले रहे हैं, जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं – आपको पता ही नहीं है कि कुरियन जी का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। यह गुजरात सरकार मना रही है। यह हमारी भाजपा सरकार ही है जो इसे मना रही है। आप यहां कुरियन जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन हमारी गुजरात सरकार उनके शताब्दी महोत्सव का आयोजन कर रही है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat. ...*(Interruptions)*... Please take your seat, Dr. John Brittas. ...*(Interruptions)*...

श्री मुरलीधर मोहोलः माननीय उपसभापति महोदय, एक माननीय सदस्य ने कहा कि वर्गीज कुरियन बीजेपी के नहीं थे, इसलिए उनका नाम नहीं दिया गया। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति किसी भी क्षेत्र में बड़े कार्य करने वाले व्यक्ति का सम्मान करने की है। हमारे मन में उनके प्रति आदर और सम्मान की भावना है। लेकिन जब किसी क्षेत्र में सबसे बड़े योगदानकर्ता का नाम दिया जाता है, तो सहकारी आंदोलन में त्रिभुवन दास जी का योगदान सर्वोपरि माना जाता है और इसलिए यह नाम दिया गया है। यह हमारे लिए गौरव की बात है।

माननीय उपसभापति महोदय, कुछ सदस्यों ने इस विश्वविद्यालय के संचालन के बारे में भी पूछा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय को संसद के अधिनियम के तहत "इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस" का दर्जा दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र में शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों को unified और standardize करना होगा।

यह राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय सहकारिता क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान के कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित करेगा। विश्वविद्यालय के संचालन के लिए चांसलर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और अन्य आवश्यक अधिकारियों की नियुक्ति प्रस्तावित है।

माननीय उपसभापति महोदय, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े शैक्षणिक कार्यों के साथ-साथ research and development की गतिविधियां भी शामिल होंगी। इस विश्वविद्यालय में आवश्यकता के अनुसार देश के विभिन्न स्थानों पर sector-specific schools स्थापित होंगे। यह विश्वविद्यालय अलग-अलग राज्यों के प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी भी करेगा। दसवीं, बारहवीं उत्तीर्ण विद्यार्थी भी इस विश्वविद्यालय के कोर्स कर पाएंगे। इस विश्वविद्यालय में Graduate, Post Graduate, Ph.D., and short-term courses भी प्रस्तावित हैं। इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में विश्व के सहकारिता क्षेत्र की best practices भी शामिल होंगी। उपसभापति महोदय, राज्यों के सहकार का केन्द्रीयकरण चल रहा है, राज्यों की सहकारिता का क्या होगा, ऐसी कुछ शंकाएं इस सदन में उपस्थित हुईं, लेकिन मैं उनको आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं, उनको अवगत कराना चाहता हूं कि त्रिभुवन सहकारी

विश्वविद्यालय देश के विभिन्न राज्यों के मौजूदा सहकारी शिक्षण और अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं को hub- and-spoke model पर affiliate करेगा। यह affiliation पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। उसमें एक बात और है कि हमने यह भी प्रावधान किया है कि पूरे सहकारिता का शिक्षण पूरे देश में जिस-जिस राज्य में आएगा, उसमें प्रांतीय भाषा में दिया जाएगा। भविष्य में आवश्यकता के अनुसार विभिन्न राज्यों में नए outline campuses भी स्थापित किए जाने पर विचार किया जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम जरूरत के अनुसार प्रांतीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा।

महोदय, हमारे महाराष्ट्र के एक सदस्य यहां VAMNICOM का इश्यू उठाकर चले गए। मुझे लगता था कि उनको सुनना चाहिए था। VAMNICOM का महत्व हमारी दृष्टि से अच्छा इंस्टीट्यूट है और यह यूनिवर्सिटी होने के बाद VAMNICOM, त्रिभुवन विश्वविद्यालय का important part होगा। यह विश्वविद्यालय hub-and-spoke model पर कार्य करेगा। हमारा VAMNICOM का एक प्रमुख सेंटर, पुणे में काम करेगा। सर, कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर कुछ बातें रखी थीं कि पश्चिम बंगाल और बाकी राज्यों के सभासद यहां थे, उन्होंने की। हमारे यहां केन्द्रीयकरण का काम चल रहा है, राज्यों के साथ समन्वय नहीं, मैंने अभी कहा कि हम जो model by-laws लाए, आप सदस्यों को यह बात मालूम नहीं है कि आपकी सरकार ने इस model by-laws को भी adopt किया है। उसके साथ हम काम कर रहे हैं। यह सरकार के समन्वय के कारण ही होता है। हमारे ज्येष्ठ सदस्य ने कहा कि केन्द्रीयकरण किया जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्त रूप से अधिनियमन, परिनियम और अध्यादेशों के अधीन कार्य करेगा और इससे वित्तीय एकेडेमिक और प्रशासनिक स्वायत्तता होगी। हम सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के साथ काम कर रहे हैं। यह विश्वविद्यालय योग्य श्रम बल तैयार करेगा, जो सभी राज्यों के सहकारी समितियों के काम आएगा।

उपसभापति महोदय, मुझे लगता है कि इस सदन में पिछले चार घंटे से चर्चा चल रही है, तो उस पर मेरा यह निवेदन था कि भावना सभी की अच्छी है, सभी की भावना एक ही है कि विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ सुझाव दिए, इस विश्वविद्यालय के लिए यहां पर guidelines रखी गई हैं। मैं अंत में एक बार फिर से इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद करता हूं। इस बिल के माध्यम से देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। आने वाले समय के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी हमारे सहकारिता क्षेत्र में कार्य करने के लिए skilled manpower का सृजन करेगी, देश में cooperative spirit को बढ़ावा देगी और भविष्य के लिए cooperative leadership को तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देगी। हमारे प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारा सहकारिता मंत्रालय अपना योगदान देगा। इसी अपेक्षा के साथ मैं यह अनुरोध करता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर आज एक स्वर में देश के सहकारिता क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने वाले इस त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के बिल का समर्थन करें और सर्वसम्मति से इस बिल को पारित करें। फिर से आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to establish the Institute of Rural Management Anand, as a University to be known as the "Tribhuvan" Sahkari University and to declare the same as an institution of national importance; to impart technical and management education and training in co-operative sector: to promote co-operative research and development and to attain standards of global excellence therein in order to realise the vision of "Sahkar Se Samriddhi" and to strengthen the co-operative movement in the country through a network of institutions, and also to declare the Institute as one of the Schools of the University and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 4, there is one Amendment (No. 1) by Dr. John Brittas. Are you moving it?

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I am certainly moving it. I move:

(No. 1) That at page 3, line 41, *after* the words, "University may", the words, ", after consultation with and concurrence of the concerned State Government,", be *inserted*.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 4 was added to the Bill.

Clauses 5 to 8 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 9, there is one Amendment (No. 2) by Dr. John Brittas. Are you moving the amendment?

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I move:

(No. 2) That at page 9, lines 3 to 20, be *deleted*.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 9 was added to the Bill.

Clauses 10 to 53, the First Schedule and the Second Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Murlidhar Mohol to move that the Bill be passed.

श्री मुरलीधर मोहोल: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. on Wednesday, 2nd April, 2025.

The House then adjourned at eighteen minutes past eight of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 2nd April, 2025.